राजस्थान समसामयिकी अप्रैल, 2023

संजीव वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड करें
राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एवं बजट का सार संग्रह;
राजस्थान, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिकी (प्रत्येक माह)
साथ ही संजीव वेबसाइट से आप E-Book भी खरीद सकते हैं।
visit us at : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान समसामयिकी अप्रैल, 2023
(Current News from Daily Newspapers)

Newspaper of 1 April, 2023

■ धौलपुर रेलवे जंक्शन से संचालित होने वाली 113 साल पुरानी नैरोगेज (छोटी लाइन) ट्रेन अब नहीं चलेगी; ट्रेन ने अपना अंतिम सफर पूरा किया–

31 मार्च, 2023 को धौलपुर रेलवे जंक्शन से संचालित होने वाली 113 साल पुरानी नैरोगेज (छोटी लाइन) ट्रेन ने अपना अंतिम सफर पूरा किया। रेलवे ने नैरोगेज से ब्रॉडगेज आमान परिवर्तन के चलते धौलपुर, सरमथुरा एवं मोहारी तांतपुर खण्ड की सभी सेवाएं 1 अप्रैल, 2023 से बंद करने का निर्णय किया है।

धौलपुर रेलवे जंक्शन से 89 किमी. रेलमार्ग पर दौड़ने वाली नैरोगेज ट्रेन की शुरुआत तत्कालीन महाराजा धौलपुर ने 1908 ई. में की थी।

■ राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा वित्त और विनियोग विधेयक को मंजूरी देने के साथ ही बजट को मंजूरी मिली–

30 मार्च, 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने वित्त और विनियोग विधेयक को मंजूरी दे दी है। जिससे बजट को मंजूरी मिल गयी है। राज्य सरकार ने 6 विधेयक भी राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजे हैं।

■ एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की–

राजस्थान में प्रतियोगी और सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) के गठन को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इससे प्रकरणों मे लिप्त दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके संचालन के लिए 39 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में बजट 2023-24 में घोषणा की थी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार पूर्व में राज्य विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2022 पारित करा चुकी है। इसमें पेपर लीक एवं नकल से संबंधित परीक्षार्थियों को कारावास, सार्वजनिक परीक्षाओं से डिबार, दोषियों की सम्पत्ति ध्वस्त जैसे प्रावधान किए गए हैं।

■ राजस्थान में नई साइकिल नीति लागू होगी–

राजस्थान सरकार सड़कों पर बढ़ते वाहनों के कारण बढ़ रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए नई साइकिल नीति ला रही है।

इस नीति के तहत पहले सरकारी वाहनों में कटौती करते हुए मंत्रियों व अफसरों को सचिवालय तक साइकिल से आने जाने के लिए कहा जाएगा तथा अन्य सरकारी कर्मचारी भी, जो साइकिल से अपने कार्यालय आना-जाना चाहेंगे उन्हें विशेष भत्ता देते हुए ड्यूटी में दो घंटे की रियायत दी जाएगी।

वर्तमान में मंत्रियों व अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अफसरों के सरकारी वाहन मोटर गैराज में भेज दिए गए हैं। इन सबको साइकिल से ही सचिवालय आने जाने का कहा गया है। आपात स्थिति में सरकारी वाहन प्रयोग में लाया जा सकेगा।

गौरतलब है कि इस नीति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी केवल जयपुर में ही लागू किया जाएगा। जयपुर में साइकिल ट्रेक के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। राज्य सरकार के जो मंत्री, अफसर व कार्मिक साइकिल सवारी पसंद करेंगे, उन्हें सरकार अपनी ओर से साइकिल उपहार में देगी।

■ मतदान नहीं करने वालों को प्रति यूनिट 1 रुपए महँगी बिजली मिलेगी; राजस्थान में विधानसभा चुनाव से लागू होगा–

हाल ही में चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि चुनावों में मतदान नहीं करने वालों को प्रति यूनिट 1 रुपए महँगी बिजली मिलेगी। शीघ्र ही इसकी अधिसूचना जारी होगी। ऐसी मतदाताओं के लिए अलग टैरिफ तैयार की जा रही है। ऐसा चुनावों में अधिकाधिक मतदान के लिए किया जा रहा है।

यदि परिवार में एक भी मतदाता वोट नहीं करता है जो उसके बिजली के बिल में अतिरिक्त राशि जुड़कर आएगी।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग का यह निर्णय राजस्थान में इसी विधानसभा चुनाव से होगा तथा आगामी समय में अन्य राज्यों पर भी लागू होगा।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

Newspaper of 2 April, 2023

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न योजनाओं को मंजूरी प्रदान की–

- राज्य के 8 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को संकर बाजारा बीज उपलब्ध कराया जाएगा। 'कृषक कल्याण कोष' से 10 करोड़ रुपए तथा 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' से 6 करोड़ रुपए (कुल 16 करोड़ रुपए) के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत–
  - 'राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन' के तहत प्रदेश के बाजरे की कम उत्पादकता वाले 15 जिलों में मिनिकिट्स का वितरण किया जाएगा।
  - संकर बाजरा बीज वितरण वाले जिलों में अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, टोंक, झुंझुनूँ, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर एवं सिरोही शामिल हैं।
- राज्य के लक्खी मेलों में जाने के लिए श्रद्धालुओं को किराए में 50% रियायत (छूट) के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  - राजस्थान रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में मेला अवधि के दौरान किराए में छूट मिलेगी।
  - अजमेर में पुष्कर मेला और दरगाह उर्स, करौली में कैलादेवी मेला, भरतपुर में झील का बाडा, जैसलमेर में श्रीरामेदवरा मेला, सीकर में खाटूश्यामजी, चूरू में सालासर बालाजी, हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी, डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, सवाईमाधोपुर में रणथम्भौर गणेश जी, टोंक में डिग्गी कल्याण जी, अलवर में भर्तृहरि व पाण्डुपोल, श्रीगंगानगर में बूढ़ा जोहड़ गुरूद्वारा, बीकानेर में फाल्गुन और चित्तौगड़गढ़ में सांवलिया सेठ-जलझूलनी एकादशी मेलों के लिए छूट का प्रावधान किया गया है।
- 'मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना' (500 रुपए में रसोई सिलेंडर) के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस पर 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
  - इससे राज्य के 73 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे।
  - योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1 अप्रैल से सस्ती दर पर प्रतिमाह एक सिलेण्डर मिल सकेगा।
  - राज्य सरकार उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी परिवारों को प्रति गैस सिलेण्डर 410 रुपए की सब्सिडी देगी।
  - बीपीएल परिवारों के लिए प्रति सिलेण्डर सब्सिडी 610 रुपये होगी।
  - लाभार्थी के जनआधार से जुड़े खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरित की जाएगी।

'मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना' के पोर्टल का शुभारम्भ किया गया–

1 अप्रैल, 2023 को राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 'मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना' के पोर्टल का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल से राज्य के विशेष योग्यजनों को 5000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। दिव्यांगजनों को 5000 स्कूटी नि:शुल्क देने की घोषणा राज्य बजट 2023-24 में की गई है।

गौरतलब है कि ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने से आवेदन करने की प्रक्रिया तथा दस्तावेजों संबंधी समस्याएँ दूर होंगी तथा स्कूटी वितरण योजना अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी।

Newspaper of 3 April, 2023

राजस्थान में अब शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी नि:शुल्क शिक्षा मिलेगी; राज्य सरकार ने फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की–

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12वीं कक्षा तक के छात्रों के नि:शुल्क शिक्षा हेतु फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अब राजस्थान में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों के 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी नि:शुल्क शिक्षा मिलेगी। इस पर 46 करोड़ रुपए व्यय होंगे।

- आरटीई के माध्यम से कक्षा 1-8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान है।
- राज्य बजट 2022-23 में राजस्थान सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9-12 तक निजी सकूलों में नि:शुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था।
- इसी क्रम में अब छात्रों को भी कक्षा 1-12 तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। राज्य बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

Newspaper of 4 April, 2023

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला निधि से उपलब्ध होने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की–

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

अप्रैल, 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, इसके लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।

इस प्रस्ताव के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिला समानता दिवस पर 'राजस्थान महिला निधि' की शुरूआत की थी।

Newspaper of 5 April, 2023

■ राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे–

4 अप्रैल, 2023 को राजस्थान में जल संरक्षण एवं भूजल सिंचाई की दिशा में नवाचार के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान में राजकीय भवनों पर 'अटल भूजल योजना' के तहत फिजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।

ये राज्य के 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे। इनसे वर्षा जल का संचयन एवं संरक्षण होगा।

■ सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के तहत बीज वितरण और उत्पादन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी–

हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के तहत बीज वितरण और उत्पादन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य सरकार 15 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के 1.25 लाख से अधिक किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 35 हजार क्विंटल बीज नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

इस योजना में गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ एवं उड़द के बीज उपलब्ध होंगे। योजना के लिए 15 करोड़ रुपए कृषक कल्याण कोष से वहन किए जाएंगे।

गौरतलब है कि 'राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन' के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।

Newspaper of 6 April, 2023

■ सीएम अशोक गहलोत ने सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए सर्विस मॉडल पर 500 बसों की सेवाएँ लेने को मंजूरी दी; संचालन के लिए 132.24 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी–

राजस्थान में नगरीय ट्रांसपोर्ट सेवा को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में शीघ्र ही सर्विस मॉडल पर 500 बसों की सेवाएँ लेने को मंजूरी दी है। इन बसों के संचालन के लिए 132.24 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है।

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को एकीकृत कर '**राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन**' का गठन करेगी।

■ राजस्थान के पुलिस थानों में 'पैरा लीगल वॉलन्टियर' नियुक्त होंगे–

हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने राज्यभर में लापता बच्चों, उनके विरुद्ध अपराधों आदि की स्थिति में पीड़ितों को पुलिस थानों पर विधिक सहायता के लिए पुलिस थानों में 'पैरा लीगल वॉलन्टियर' नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। प्रारम्भिक चरण में जिला मुख्यालय के 66 पुलिस थानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के 99 पुलिस थानों में एक-एक (कुल-165) वॉलन्टियर नियुक्त होंगे। पैरा लीगल वॉलन्टियर को प्रतिमाह 15000 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा।

Newspaper of 7 April, 2023

■ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की–

राजस्थान में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्रोतों पर निगरानी के लिए 'राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय' के गठन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल और प्रशासनिक विभाग वित्त (राजस्व) विभाग होगा।

इस निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण, अनुसंधान, जांच और अभियोजन से संबंधित प्रकरण होंगे।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

इस निदेशालय के माध्यम से भूमि पर अवैध कब्जे, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी या अनियमितता, बैंक, बीमा या जमापूंजी संबंधी कार्य में धोखाधड़ी या अनियमितता, दिवालिया होने की झूठी घोषणा, फर्जी कम्पनियों के गठन, सरकारी साख समितियों के कार्य में धोखाधड़ी करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।

■ **वर्ष 2023-24 के लिए 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' का नया पोर्टल शुरू किया गया; 30,000 प्रतियोगी परिक्षार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग का लाभ मिलेगा–**

6 अप्रैल, 2023 को वर्ष 2023-24 के लिए 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' का नया पोर्टल शुरू किया गया है। इस नए पोर्टल का शुभारम्भ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने वर्चुअल रूप से किया। इसके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले 30,000 अभ्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग का लाभ दिलाया जाएगा। परीक्षावार कोचिंग के निम्न अभ्यर्थी लिए जाएंगे–

परीक्षा	अभ्यर्थियों की संख्या
यूपीएसी परीक्षाएँ	600
आरएएस एवं सम्बद्ध सेवा	1,500
सब इंस्पेक्टर या लेवल-10	2,400
शिक्षक भर्ती (रीट)	4,500
लेवल-5 से लेवल-10 भर्ती	3,600
पुलिस कांस्टेबल	2,400
मेडिकल और इंजीनियरिंग	12,000
क्लैट और अन्य परीक्षाएँ	3,000
कुल	**30,000**

Newspaper of 8 April, 2023

■ **राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बनी–**

हाल ही में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बनी है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 100 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड हो गए हैं।

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड विशेष–

- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा 15 छोटे शहरो में 3 हजार नए आवास बनाकर आवंटित किए गए हैं।
- कोरोना महामारी के पश्चात् मात्र 2 वर्ष में मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के 576 आवासों का आवंटन किया गया है।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के 7 प्रोजेक्ट के 4,500 फ्लैट्स पूर्ण होने वाले हैं, जिनका शीघ्र आवंटन होना है।
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लगभग एक हजार मकान निर्माणाधीन हैं, जिनका भी आवंटन जून माह के अंत तक होगा।
- आवासन मंडल द्वारा वर्तमान में 4,500 आवासों के लिए 27 योजनाएँ लाई गई हैं।
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा है।

Newspaper of 9 April, 2023

■ **राजस्थान सरकार ने राज्य में नए पुलिस कार्यालय, थाने एवं चौकियां खोलने की मंजूरी प्रदान की–**

8 अप्रैल, 2023 को राजस्थान सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत करने के लिए नए पुलिस कार्यालय, थाने एवं चौकियां खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए 201 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति के साथ 1369 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय–वैर (भरतपुर), परबतसर (नागौर), खैरवाड़ा (उदयपुर), एडीएफ (धौलपुर) एवं लालसोट (दौसा) में खुलेंगे।

नए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय–अरनोद (प्रतापगढ़), तालेड़ा (बूंदी), पहाड़ी (भरतपुर), गंगाशहर (बीकानेर), रामसर (बाड़मेर), बौंली (सवाईमाधोपुर), खण्डेला (सीकर), अजीतगढ़ (सीकर), सिवाना (बाड़मेर) एवं आहोर (जालोर) में खुलेंगे।

नए महिला पुलिस थाने–डीडवाना (नागौर), नावां (नागौर) एवं कोटपूतली (जयपुर) में खुलेंगे।

नए शहरी पुलिस थाने–श्रीनाथजी (राजसमंद), वैशाली नगर (अलवर), मुक्ता प्रसाद नगर (बीकानेर), बयाना सदर (भरतपुर) और गोकुलपुरा (सीकर) में खुलेंगे।

नए ग्रामीण पुलिस थाने–सदयाल (अलवर), हदां (बीकानेर), राहुवास (दौसा), तनोट (जैसलमेर) एवं गोठड़ा (झुंझुनूँ) में खुलेंगे।

■ **करौली जिले में गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के लिए नवाचार के तहत आंचल अभियान शुरू किया गया–**

करौली जिले में नवाचार के तहत जिला प्रशासन द्वारा गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल के लिए 'आंचल अभियान' शुरू किया गया है, इस अभियान के तहत–

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- इससे 13,144 महिलाएँ लाभान्वित हो चुकी हैं।
- अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की गई।
- स्वयं को तनाव मुक्त रखने के लिए महिलाओं की काउंसलिंग की गई।

Newspaper of 10 April, 2023

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी–

हाल ही में राज्य में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्रोतों पर अधिक अधिकारीक निगरानी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी की है। निदेशालय में 107 नए पदों का सृजन होगा जिसमें महानिदेशक/आयुक्त का एक, अतिरिक्त निदेशक के चार, संयुक्त निदेशक के 10 तथा उपनिदेशक के 20 पद तथा अन्य कार्मिकों के पद सृजित होंगे।

इस निदेशालय द्वारा आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, जांच और अनुसंधान, अभियोजन के कार्य किए जाएँगे।

गौरतलब है कि राजस्व आसूचना निदेशालय पहले से ही संचालित है। राज्य बजट 2022-23 में आर्थिक अपराध निदेशालय की घोषणा की गई थी। अब दोनों का सम्मेलन करने से मानव संसाधन तथा अपराधों की जांच में भी विश्लेषणात्मक क्षमता का उचित उपयोग होगा।

Newspaper of 11 April, 2023

राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया–

राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर राजस्थान में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। अब तक ज्योतिबा फुले जयंति पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया हुआ था। इससे पूर्व राज्य सरकार ने 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण की जयंती पर भी ऐच्छिक अवकाश को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। गौरतलब है कि राजस्थान में अब राजकीय सेवाओं केलिए सार्वजनिक अवकाश की संख्या 30 एवं ऐच्छिक अवकाश की संख्या 20 हो गई है।

राजस्थान सरकार 2,000 टैक्स मित्र नियुक्त करेगी; ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा–

राज्य सरकार व्यापारियों एवं उद्यमियों को जीएसटी, वैट के लेन-देन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत के लिए 2,000 'टैक्स मित्र' नियुक्त करेगी। जिससे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा मूल्य वर्धित कर (वैट) जमा करना आसान होगा।

राज्य सरकार टैक्स लेन-देन करने वालों को 'सेल्फ टैक्स स्क्रूटनी' की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी विकसित करेगी।

टैक्स मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक होगी।

गौरतलब है कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 में जीएसटी, वैट प्रक्रियाओं में सुगमता के लिए इसकी घोषणा की गई थी।

Newspaper of 12 April, 2023

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नवाचार करते हुए व्हाट्सएप चैट बोट की हैल्पलाइन शुरू की–

हाल ही में 10 अप्रैल 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नवाचार व्हाट्सएप चैटबोट की हैल्पलाइन शुरू की है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को कहीं भी, कभी भी की तर्ज पर योजनाओं से संबंधित सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

व्हाट्एसएप चैट बॉट के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति, पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। मोबाइल नंबर 9462745980 पर व्हाट्सअप संदेश भेजकर योजनाओं के बारे में, पात्रता मापदंड, फायदे, आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण अवस्था, आवेदन की वर्तमान स्थिति और भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा–

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम व टीएचडीसी इंडिया राजस्थान में 10 हजार मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित करेंगे। इसके लिए संयुक्त उपक्रम 'ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड' बनाया गया है। इससे राजस्थान में 40 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा।

'पीएम श्री' योजना में राजस्थान के देश में सर्वाधिक 402 विद्यालयों का चयन हुआ–

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। नई

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत खोले जा रहे नवीन 'पीएमश्री' स्कूलों की योजना में राजस्थान को देश में सर्वाधिक 402 सरकारी विद्यालयों के चयन के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस योजना में पूरे देश में 14 हजार 597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान के 402 विद्यालय भी हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा के 346 और प्रारम्भिक शिक्षा के 56 राजकीय विद्यालयों का चयन हुआ है। इन सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होगी। इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेंगी। पीएमश्री योजना के तहत वर्ष 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा।

गौरतलब है कि पीएमश्री योजना में राज्य के कुल 718 विद्यालयों को शामिल किया जाएगा।

Newspaper of 13 April, 2023

■ राजस्थानी की पहली व देश की 14वीं वन्दे भारत (हाईस्पीड) ट्रेन दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से अजमेर के बीच शुरू हुई–

12 अप्रैल, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान की पहली हाइस्पीड ट्रेन वन्दे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर रेलवे जंक्शन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य प्रबुद्ध लोगों ने वन्दे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की 14वीं वन्दे भारत रेल है। यह अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच वाया-जयपुर, अलवर, गुरुग्राम होकर चलेगी। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 कि.मी. प्रति घंटा है, जिसे वर्तमान में 110 कि.मी. प्रतिघंटा पर चलाया जा रहा है।

■ राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक-2022 (RTH) एवं अन्य 3 कुल 4 विधेयकों को मंजूरी दी–

12 अप्रैल, 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक एवं अन्य तीन सहित कुल 4 विधेयकों को मंजूरी दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधि विभाग ने इन विधेयकों को कानून बनने की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी से पूर्व इन्हें विधानसभा में पारित किया गया था।

राज्यपाल की मंजूरी मिलने वाले 4 विधेयक निम्न हैं–

- 'राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022'
- 'राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2023'
- 'बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2023'
- 'राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापन और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023'

गौरतलब है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने 'राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023' को केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजा है।

Newspaper of 14 April, 2023

■ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झील-तालाब व इको सेंसटिव जोन में डीजे, पटाखों के शोरगुल सहित ध्वनि प्रदूषणकारी यंत्रों पर रोक लगाई–

हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झील-तालाबों व इको सेंसटिव जोन में डीजे, पटाखों के शोरगुल सहित ध्वनि प्रदूषणकारी यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। इसके लिए होटल संचालकों को शोर प्रदूषण मापक मीटर लगाना होगा तथा मॉनिटरिंग के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल को विशेष प्रोटोकॉल व एप बनाना होगा। इससे निम्न क्षेत्र प्रभावित होंगे–

- उदयपुर की फतहसागर झील व सज्जनगढ़ अभयारण्य का इको सेंसटिव जोन।
- **जयपुर**-नारहगढ़, झालाना, जमवारामगढ़, आमागढ़, रामगढ़ बांध, नेवटा, कूकस व चंदलाई बांध व आसपास का क्षेत्र, मानसागर झील व करीबी क्षेत्र, सेंट्रल पार्क खोले के हनुमानजी व आसपास का क्षेत्र, शूटिंग रेंज, गलता तीर्थ क्षेत्र, आमेर।
- **अजमेर**–आनासागर झील
- **कोटा**–चंबल बांध
- **अलवर**–अरावली पर्वत शृंखला क्षेत्र व सरिस्का आदि।
- **भरतपुर**–घना अभयारण्य क्षेत्र
- **सवाई माधोपुर**–रणथम्भोर अभयारण्य क्षेत्र
- **झालावाड़**–मुकंदरा हिल्स क्षेत्र

■ राजस्थान सरकार द्वारा बहुमंजिला इमारतों के लिए जल कनेक्शन नीति जारी की गई; जल कनेक्शन का शुल्क 25 रुपए प्रति वर्गफुट होगा–

13 अप्रैल, 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा बहुमंजिला इमारतों के लिए जल कनेक्शन नीति जारी की गई है। जल कनेक्शन नीति में बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों को जल कनेक्शन का शुल्क 25 रुपए प्रति वर्गफुट के अनुसार देना होगा।

■ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध देश का आइकोनिक बांध बना–

हाल ही में राज्य का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध देश का आइकोनिक (प्रतिष्ठित) और फेमस (प्रसिद्ध) बांध बन गया है। केन्द्रीय जल आयोग ने कुल 17 बांधों को

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

आइकोनिक और फेमस बांध माना है, जिसमें राजस्थान का एकमात्र बांध राणाप्रताप सागर शामिल है। इस बांध का पूर्ण भराव स्तर 1157.50 फीट, ऊँचाई 177 फीट तथा आधार क्षमता 1.27 लाख एकड़ फीट है।

केन्द्रीय जल आयोग की सूची के अनुसार देश के 17 फेमस बांध निम्न है–

- राणाप्रताप सागर बांध — राजस्थान
- कृष्णराज सागर डैम — कर्नाटक
- कल्लनई बांध — तमिलनाडू
- हीराकुड बांध — उड़ीसा
- रिहंद बांध — उतरप्रदेश
- तुंगभद्रा बांध — कर्नाटक
- मैथन बांध — झारखंड
- इडुक्की बांध — केरल
- भाखड़ा बांध — पंजाब
- नागार्जुना सागर — तेलंगाना
- कोयना बांध — महाराष्ट्र
- उकाई बांध — गुजरात
- सरदार सरोवर डैम — गुजरात
- मेटूर बांध — तमिलनाडु
- भवानीसागर डैम — तमिलनाडु
- अलमट्टी बांध — कर्नाटक
- उजानी बांध — महाराष्ट्र

Newspaper of 15 April, 2023

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राजस्थान को बेहतर क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय सम्मान मिले–

राजस्थान सरकार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बेहतर क्रियान्वयन के लिए दो राष्ट्रीय सम्मान मिले है, जिसमें–

- राजस्थान को डीजी के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है।
- लम्बित प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला है।

गौरतलब है कि राज्य में फसल बीमा योजना के तहत पिछले 4 वर्षों में 18,500 करोड़ रुपए से अधिक बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं तथा वर्ष 2022-23 में 80% पॉलिसी 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' शिविर में वितरित की गई है।

राज्य के राजस्व मंडल (अजमेर) में ई-फाइलिंग सिस्टम पूरी तरह से लागू हुआ; सभी कामकाज ऑनलाइन होंगे–

हाल ही में राज्य के राजस्व मंडल (अजमेर) में ई-फाइलिंग प्रणाली को लागू किया गया है यहाँ अब फाइल से संबंधित सारा काम ऑनलाइन हो गया है। राजस्व मंडल में ई-फाइलिंग प्रणाली के तहत–

- करीब 17,000 से अधिक फाइलें राजकाज पोर्टल के जरिए ऑनलाइन की गई है।
- पत्रावलियों का पूरी सुरक्षा एवं पारदर्शिता के साथ निस्तारण किया जा रहा है।
- फाइलों के निस्तारण में लगने वाला समय पहले की तुलना में कम हो गया है।
- अब टेबल्स से फाइल्स की जगह कम्प्यूटर ने ले ली है।
- मंडल में ई-फाइलिंग सिस्टम लागू होने से हर दिन पलक झपकते ही फाइलों का निस्तारण केवल एक क्लिक पर करना संभव हो रहा है।

'मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना' की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया; राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट मिलेंगे–

हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना' की कार्ययोजना का अनुमोदन किया है। इसके तहत–

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को लगभग 370 रुपये प्रति पैकेट की लागत का फूड पैकेट निःशुल्क दिया जाएगा।
- राज्य सरकार फूड पैकेट देने के लिए लगभग 392 करोड़ रुपये मासिक व्यय करेगी।
- योजना के पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंपों में होगा।
- इसमें सहकारिता विभाग के कॉनफैड द्वारा सामग्री क्रय कर पैकेट तैयार किए जाएंगे और उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इन फूड पैकेटों का वितरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाएगा।

निःशुल्क फूड पैकेट में निम्न सामग्री होगी–

चना दाल	1 किलो
चीनी	1 किलो
नमक	1 किलो
खाद्य तेल	1 लीटर
मिर्ची पाउडर	100 ग्राम
धनिया पाउडर	100 ग्राम
हल्दी पाउडर	50 ग्राम

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

■ **राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) कनोता और नेवटा बांध को आइकॉनिक इको-एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित करेगा–**

राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) की ओर से कानोता और नेवटा बांध को आइकॉनिक इको-एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे यहाँ पर्यटक तेज रफ्तार बोटिंग का आनंद ले सकेंगे तथा यहाँ केरल की तर्ज पर बोट हाउस, जार्बिग, पैटून बोट, बनाना बोट का संचालन किया जाएगा।

इसके साथ ही यहाँ पर्यटकों के लिए खाने-पीने के लिए चौपाटी विकसित की जाएगी। यह सभी कार्य पीपीपी मोड पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

Newspaper of 16 April, 2023

■ **मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री गुरू नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी–**

13 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैसाखी पर्व के अवसर पर राज्य में श्री गुरू नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, यह बोर्ड प्रदेश में सिख समुदाय के सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन के लिए कार्य संपादित करेगा। इसके लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा श्री गुरू नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।

श्री गुरू नानक सिख कल्याण बोर्ड विशेष–

- इस बोर्ड का उद्देश्य सिख समुदाय के उत्थान के लिए योजनाएँ प्रस्तावित करना और रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव देना है।
- यह बोर्ड सिख समुदाय के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी सुझाव देगा। साथ ही, सिख समुदाय की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय के परम्परागत व्यवसायों को आधुनिक रूप देने के लिए सुझाव देगा।
- बोर्ड सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योजनाओं में समुदाय की भागीदारी, नई योजनाओं की प्रगति और इनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के समाधान के लिए निरंतर समीक्षा करेगा।
- श्री गुरू नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच सदस्यों सहित सात गैर सरकारी सदस्य होंगे।
- विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

Newspaper of 17 April, 2023

■ **राज्य सरकार ने कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनामी राशि में वृद्धि की–**

16 अप्रैल, 2023 को राज्य सरकार ने प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनामी राशि में वृद्धि की है, अब निम्न इनामी राशि की घोषणा पुलिस अधिकारी कर सकेंगे–

अधिकारी	पहले राशि	वर्तमान राशि
पुलिस महानिदेशक	1 लाख	5 लाख
अतिरिक्त महानिदेशक	50 हजार	1 लाख
पुलिस रेंज महानिरीक्षक	10 हजार	50 हजार
जिला पुलिस अधीक्षक	5 हजार	25 हजार

■ **राजस्थान के वरिष्ठ सम्पादक प्रदीप शेखावत हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त बने–**

हाल ही में राजस्थान के वरिष्ठ सम्पादक प्रदीप शेखावत हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। उन्हें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

■ **कोटा की नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड-2023 बनीं–**

हाल ही में कोटा की नंदिनी गुप्ता 59वें फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी कार्यक्रम में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड-2023 बनीं है। इनसे पूर्व 2019 में जयपुर की सुमन ने यह खिताब जीता था। नंदिनी मिस राजस्थान भी रह चुकी हैं। इस प्रतियोगिता में मणिपुर की स्ट्रेला थौनाओजम लुवांग को सैकण्ड रनर-अप व दिल्ली की श्रेया पूजा को फर्स्ट रनर-अप घोषित किया गया।

Newspaper of 18 April, 2023

■ **प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली; एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद सभी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे–**

राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी परीक्षाओं में बैठा जा सकेगा।

राजस्थान सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपए तथा शेष श्रेणी के लिए 400 रुपए शुल्क निर्धारित किया है।

वर्तमान में निम्न आवेदन शुल्क लिया जा रहा है–

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड	
सामान्य वर्ग/क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग	₹ 450
राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा/एमबीसी/ईडब्ल्यूएस	₹ 350
समस्त विशेष योग्यजन/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग	₹ 250
परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम	₹ 250

राजस्थान लोक सेवा आयोग	
सामान्य/क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी वर्ग	₹ 350
नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के ओबीसी/एमबीसी	₹ 250
नि:शक्तजन, एससी/एसटी वर्ग	₹ 150

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी। इससे सरकार पर ₹ 200 करोड़ का भार आएगा।

■ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेन्टर (आरआईसी) का उद्घाटन किया–

17 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के झालाना क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशल सेंटर (आरआईसी) का उद्घाटन किया। इसका शिलान्यास वर्ष 2013 में हुआ था। यह दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर तैयार हुआ है।

आरआईसी के रखरखाव के लिए सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इसमें एक-एक ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर, तीन कॉन्फ्रेंस रूम, ई-लाइब्रेरी तथा लग्जरी रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी।

राजस्थान इन्टरनेशनल सेंटर की बिल्डिंग के इंटीरियर को हैरिटेज लुक में बनाया गया है। यहाँ ऑडिटोरियम की दीवारों पर जैसलमेर स्थित पटवों की हवेलियों की झलक देखने को मिलेगी। कन्वेंशन हॉल में सिटी पैलेस की झरोखे व हवामहल की खिड़कियाँ और मिनी ऑडिटोरियम को मारवाड़ पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। यहाँ का कॉन्फ्रेस हॉल जोधपुर के मंडोर उद्यान में पुरातन कला के मेहराब व स्मारक पर आधारित है।

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में निम्न सुविधाएँ है–

सुविधा		सीट/क्षमता
• ऑडिटोरियम	—	750
• कन्वेंशन सेंटर	—	500
• 2 मिनी ऑडिटोरियम	—	185-185
• एग्जिबिशन एरिया	—	500
• 3 कॉन्फ्रेंस हॉल	—	110, 90, 60
• ई-लाइब्रेरी	—	100
• 3 लेक्चर हॉल	—	55, 55, 55
• 2 रेस्टोरेंट	—	156, 25
• पार्किंग	—	240

■ राजस्थान में 23 जून, 2023 से राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन होगा, मुख्यमंत्री ने 130 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी–

राजस्थान में 23 जून, 2023 से सम्पूर्ण राज्य में एक साथ राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलम्पिक का आयोजन होगा। इस आयोजन में लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है।

गत वर्ष हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 29 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया था।

राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक-2023 के संबंध में विशेष–

- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले खोलों का शुभारंभ 23 जून, 2023 से होगा।
- इनके लिए प्रतिभागी खिलाड़ियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
- राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलम्पिक खेलों के आयोजन की घोषणा की थी। **ग्रामीण ओलम्पिक के दौरान** प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी, खो-खो (महिला वर्ग), शूटिंग बॉल (पुरुष वर्ग), टेनिस बॉल क्रिकेट, फुटबॉल, वालीबॉल, रस्साकशी (महिला वर्ग) खेल होंगे। **शहरी ओलम्प्कि के दौरान** विभिन्न शहरी इलाकों में कबड्डी, बास्केट बॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो (महिला वर्ग), फुटबॉल (पुरुष वर्ग), वॉलीबॉल, एथलेटिक्स (100, 200 और 400 मीटर दौड़) के आयोजन होंगे।
- इन खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेशभर में खेलों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है।
- प्रतिभागियों को शारीरिक और मानसिक तनाव से दूर कर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।

Newspaper of 20 April, 2023

■ दुनिया के सबसे प्रदूषित 100 शहरों में राजस्थान के आठ शहर शामिल–

19 अप्रैल, 2023 को जारी दुनिया के सबसे प्रदूषित 100 शहरों में राजस्थान के आठ शहर शामिल है। इसमें रीयल टाइम एयरपॉल्यूशन की स्थिति के अनुसार (19 अप्रैल,

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

2023 को 5.58 P.M.) टोंक, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, पाली, अलवर, जैसलमेर तथा भिवाड़ी शामिल है।

दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में राजस्थान के 8 शहर एक नजर में–

स्थान (RANK)	शहर (CITY)	एक्यूआई
51	टोंक	244
53	जोधपुर	228
58	पाली	204
59	बीकानेर	199
61	जयपुर	194
63	अलवर	193
72	जैसलमेर	180
75	भिवाड़ी	171

■ राजस्थान में विधानसभा-2023 के चुनाव 'एम-3' ईवीएम से होंगे–

राजस्थान में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव 'एम-3' ईवीएम से होंगे, यह थर्ड जनरेशन की ईवीएम है। यह मशीन पूर्व में उपयोग में आ रही एम-2 की अपेक्षा काफी अपग्रेड है। इससे चुनाव के रिजल्ट एम-2 के मुकाबले 30 सेकण्ड पहले मिल सकेंगे। एम-3 मशीनों की यह खासियत है कि इन मशीनों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा या फिर क्रू आदि से खोलने की कोशिश करेगा तो यह बंद हो जाएगी तथा इसके चिप को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है।

गौरतलब है कि ईवीएम-3 की हैकिंग या री प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती है। एम-3 में 24 बैलेट यूनिट और 384 प्रत्याशियों की जानकारी होगी। पहले सिर्फ चार यूनिट और 64 प्रत्याशियों की जानकारी ही रखी जा सकती थी।

सबसे पहले एम-3 मशीन का प्रयोग हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में किया गया था, उसके बाद से यही मशीन प्रयोग में लायी जा रही है।

■ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया–

19 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवनिर्मित 'राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर' में नए डॉक्टरों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया तथा 'राज हेल्थ पोर्टल' का लोकार्पण किया। यह राज हेल्थ पोर्टल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई-ऑफिस के रूप में काम करेगा तथा इससे आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण करने में भी यह पोर्टल उपयोगी सिद्ध होगा।

■ मारवाड़ का प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सीहा सम्मान केन्द्रीय रेल, संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को देने की घोषणा की गई–

हाल ही में जोधपुर के पूर्व महाराजा व सांसद गजसिंह द्वारा मारवाड़ रतन पुरस्कार-2023 की घोषणा की गई ये पुरस्कार 12 मई, 2023 को जोधपुर के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। इसमें निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा–

अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार–

- **राव सीहा सम्मान**–अश्विनी वैष्णव (केन्द्रीय रेल, संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री)
- **महाराजा सर प्रताप सिंह सम्मान**–मिसेज एन-विंसेट

राष्ट्रीय पुरस्कार–

- **राव जोधा सम्मान**–राणी भटियाणी मंदिर संस्थान, रावल किशनसिंह जसोल
- **महाराजा हनवन्तसिंह सम्मान**–विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. रमेश रलिया
- **मेजर दलपतसिंह (एम.सी.) सम्मान**–असाधारण बहादुरी के क्षेत्र में सेवानिवृत्त आई.जी. मदनसिंह
- **पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान**–कालूनाथ कालबेलिया

राज्य स्तरीय पुरस्कार–

- **महाराजा विजयसिंह सम्मान**–राजस्थानी लोक संगीत के क्षेत्र में लीला देवी सोमानी को मरणोपरान्त
- **महाराजा मानसिंह सम्मान**–शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में बीकानेर के ओंकारसिंह लखावत
- **एच.एच. महाराजा उम्मेदसिंह सम्मान**–वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में डॉ. श्रवणसिंह राठौड़
- **राजदादीसा बदन कंवर भटियाणी सम्मान**–महिला सशक्तिकरण की दिशा में वरिष्ठ अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी
- **एच.एच. राजामाता कृष्णाकुमारी सम्मान**–बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अजीम प्रेमजी फाण्डेशन
- **एच. एच. गजसिंह (द्वितीय) सम्मान**–वरिष्ठ चित्रकार रतनसिंह राजपुरोहित
- **चिरंजीव युवराज शिवराजसिंह सम्मान**–क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई
- **मुहता नैणसी सम्मान**–पत्रकारिता के क्षेत्र में मारवाड़ मैगजीन को
- **पद्मश्री सीताराम लालस सम्मान**–भंवरलाल सुथार
- **डॉ. नारायणसिंह भाटी 'मालूंगा' सम्मान**–राजस्थानी भाषा (काव्य) साहित्य के उन्नयन में संत हनुमंत किंकर महाराज
- **कुंवर करणीसिंह जसोल सम्मान**–संग्रहालय विज्ञान, डिजाइन और पारम्परिक कला के क्षेत्र में डॉ. अनुप शाह।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

- **राजाराम मेघवाल सम्मान**–भूंगरा गैस त्रासदी में असाधारण योगदान के लिए मरणोपरान्त सुरेन्द्रसिंह को दिया जाएगा। यह पुरस्कार पहली बार शुरू किया गया है।

Newspaper of 21 April, 2023

■ **पंचायती राज विभाग पेपरलेस होगा**–राजस्थान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को पेपरलेस किया जाएगा जिसके तहत सभी योजनाओं की कार्यप्रणाली ई-फाइल के जरिए संचालित किया जाना प्रस्तावित है। पेपरलेस काम होने से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। हाल ही में श्रीगंगानगर जिले में स्थानीय प्रशासन ने पंचायती राज विभाग के कार्यों को ई-फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना लागू की है। इसमें राजकाज पोर्टल के जरिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

■ **राजस्थान आवासन मण्डल (RHB) को रियल एस्टेट सम्मान**–

राजस्थान आवासन मण्डल को रियल एस्टेट में बेहतर काम करने के लिए टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड दिया जाएगा। यह सम्मान केन्द्र सरकार की एजेन्सी नेशनल रियल एस्टेट डवलमेंट काउंसिल की ओर से मिलेगा।

■ **जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे**–

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस ऑगास्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनेंगे। वे हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज हैं।

Newspaper of 22 April, 2023

■ **राज्य सरकार ने पुलिस में 500 नई मोबाइल यूनिट के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी; मोबाइल पुलिस सेवा को 100 या 112 से जोड़ा जाएगा**–

21 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर 500 नई पुलिस मोबाइल यूनिट गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

- वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में इन मोबाइल यूनिट के गठन की घोषणा की थी।
- पुलिस मोबाइल यूनिट को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा।
- मोबाइल यूनिट के लिए सर्विस मॉडल पर 500 वाहन लिया जाना प्रस्तावित है।
- किसी स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए 100 अथवा 112 नंबर पर फोन कर मोबाइल पुलिस जरूरतमंद के पास पहुँचेगी।
- प्रत्येक यूनिट में 1 हैड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होंगे।
- मोबाइल पुलिस वाहनों के संचालन पर वर्ष 2023-24 में लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Newspaper of 23 April, 2023

■ **मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फसलों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी**–

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में 'राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन' के तहत फसलों की तारबन्दी जारी रखने की घोषणा की थी। इसके एवज में सीएम अशोक गहलोत ने निराश्रित पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए तारबन्दी के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य पर 444.4 करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा इसमें एक लाख किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान मिलेगा।

Newspaper of 24 April, 2023

■ **मत्स्य विभाग ने योजनाओं का लाभ देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया**–

23 अप्रैल, 2023 को मत्स्य विभाग, राजस्थान ने विभाग की योजनाओं का त्वरित और पारदर्शी तरीके से लाभ देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसान घर बैठे विभागीय योजनाओं के लिए स्वयं के एसएसओआईडी (SSO ID) अथवा ई-मित्र से माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

इस पोर्टल से निम्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे–

- मछली पालन और खारे पानी में झींगा पालन के लिए निजी जमीन पर तालाब का निर्माण
- मछली पालन पर प्रथम वर्ष में होने वाले उपादान पर खर्च
- मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना, मछली पकड़ने के शिल्प एवं साजो-सामान/नाव क्रय करने के लिए
- रिसर्कुलेटरी एक्वा-कल्चर सिस्टम, फिश फीड इकाई की स्थापना और केज कल्चर के लिए अनुदान
- आइस प्लान्ट, कोल्डस्टोरोज निर्माण और पुनरूद्धार और खुदरा मछली बाजार एवं संसाधनों के विकास
- रंगीन मछली विक्रय कियोस्क की स्थापना, प्रशीतित और इन्स्यूलेटेड ट्रक के क्रय सहित अन्य अनुदान और योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

Newspaper of 25 April, 2023

■ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में महापुरा से 'महँगाई राहत कैम्प' का उद्घाटन किया; 10 योजनाएँ जोड़ी गई एवं योजनाओं की लाभ के गारंटी कार्ड प्रदान किए गए–

24 मई, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में महापुरा, जयपुर से 'महँगाई राहत कैम्प' का उद्घाटन कर शुभारम्भ किया। यह 24 मई, 2023 से 30 जून, 2023 तक चलेगा। इसमें प्रमुख 10 कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को जोड़ने और तुरंत लाभ पहुँचाने के लिए गारंटी कार्ड लाभार्थी को दिए जा रहे हैं।

निम्न 10 कल्याणकारी योजनाओं को 'महंगाई राहत कैम्प' से जोड़ा गया है–

1. **इन्दिरा गांधी गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना**–उज्ज्वला और BPL श्रेणी के उपभोक्ताओं को ₹ 500 में गैस सिलेण्डर उपलब्ध हो सकेगा। सब्सिडी खाते में मिलेगी।
2. **मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना**–इसमें किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग पर बिजली नि:शुल्क देय होगी।
3. **मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना**–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े परिवारों को फूड पैकेट दिए जाएंगे। फूड पैकेट में दाल 1 किलो, चीनी 1 किलो, नमक 1 किलो, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और 1 लीटर खाद्य तेल मिलेगा।
4. **मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS)**–इसमें मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को 25 दिन का एवं सहरिया, कथौड़ी एवं विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
5. **इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना**–इसमें नगरीय क्षेत्रों के जरूरतमंदों को 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार का लाभ दिया जा रहा है।
6. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना**–इसमें विभिन्न पेंशन योजनाओं में न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। इसमें प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि की घोषणा भी की गई है।
7. **मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना**–इस योजना में 8 लाख वार्षिक आय वाले पशुपालकों की अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40,000 रुपए का बीमा नि:शुल्क दिया जाएगा।
8. **मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना**–इसमें प्रदेश के हर परिवार को 25 लाख रुपए तक के बीमा कवरेज का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना से जुड़े सरकारी या निजी अस्पताल में नि:शुल्क इलाज करवाया जा सकता है।
9. **मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना**–इसमें लाभार्थी के परिवार के एक सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देय है।
10. **मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना**–इसमें जून 2023 के बिल से 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने पर बिजली बिल शून्य आयेगा तथा ज्यादा उपभोग करने पर 750 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। पूर्व में 50 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री दी जा रही थी।

Newspaper of 26 April, 2023

■ राजस्थान में 23 जून, 2023 से राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक शुरू होंगे; इसके रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ किया गया–

राजस्थान में आगामी 23 जून 'अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस' से राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू होंगे। इसका समापन 29 अगस्त, 2023 को होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 25 अप्रैल, 2023 को ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। राजस्थान सरकार के खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना है।

राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक विशेष–

- इस वर्ष शहरी एवं ग्रामीण ओलम्पिक के लिए 130 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस 23 जून से खेलों का शुभारम्भ होगा और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को इनका समापन होगा।
- शहरी ओलम्पिक खेलों में तीन स्तरों पर एक ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में चार स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।
- पिछले वर्ष हुए ग्रामीण ओलम्पिक खेल युवाओं के साथ ही सभी आयु वर्ग में लोकप्रिय रहे और लगभग 30 लाख लोगों ने भागीदारी की।
- दोनों प्रतियोगियों (ग्रामीण एवं शहरी) ओलंपिक प्रकार के खेल आयोजित होंगे।

Newspaper of 27 April, 2023

■ राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान की निशानेबाज सुश्री अपूर्वी चंदेला को विधा वारिधि की मानद उपाधि दी–

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

26 अप्रैल, 2023 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में राजस्थान की निशानेबाज सुश्री अपूर्वी चंदेला को विद्या वारिधि की मानद् उपाधि प्रदान की। सुश्री अपूर्वी चंदेला को जगतगुरू रामानादाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर की ओर से यह उपाधि निशानेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित करने के लिए दी गई है। उन्होंने सुश्री अपूर्वी चन्देला का अभिनंदन किया और खेल जगत में भारत को और उपलब्धियाँ दिलवाने के लिए शुभकमानएँ दी।

Newspaper of 29 April, 2023

■ जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2023 शुरू हुआ–

28 अप्रैल, 2023 को जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2023 शुरू हुआ। यह मसाला मेला 28 अप्रैल से 7 मई, 2023 तक चलेगा। इस मेले का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी ने किया। इस मेले में देशभर के मसाले एवं अन्य उत्पाद उपलब्ध कराये गए हैं। मसाला मेले में राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों मुख्य रूप से पंजाब, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, केरल आदि सहकारी संस्थाएँ भी मसालों का प्रदर्शन कर रही हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जो गत कई वर्षों से आम लोगों को मसालों में मिलावट और कैमिकल के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सहकार मसाला मेले का आयोजन करता है। जिससे इसने राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लिया है।

Newspaper of 30 April, 2023

■ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में आर्थिक सहायता राशि 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की–

हाल ही में बजट घोषणा के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना' में आर्थिक सहायता राशि 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 25000 रुपए की गई है।

इसमें 25000 रुपए की राशि में से 21 हजार रुपये नववधू को तथा 4 हजार रुपए सामूहिक विवाह आयोजक संस्था को देय है। यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू की गई है।

इसके साथ-साथ कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाने वाले सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजकों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।

■ राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन के लिए एप शुरू हुआ–

29 अप्रैल, 2023 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री टीकाराम जूली ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन के लिए एप शुरू किया। अब इस ऐप से बिना किसी ई-मित्र फीस के नि:शुल्क स्वयं आवेदन किया जा सकेगा। इस सुविधा के लिए दो एप (RajSSP and Face RDapp)डाउनलोड करना होगा।

□□□

संजीव प्रकाशन, जयपुर
website : www.sanjivprakashan.com

संजीव®

48 वर्षों से आपका विश्वसनीय

आपकी सफलता में सदैव आपका सहयोगी

राजस्थान में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु

संजीव प्रकाशन

द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से अध्ययन कर सफलता प्राप्त करें।

- राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा एवं बजट का सार संग्रह
- 600+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह
- Total Pages - 176
- Fix Rate - ₹100

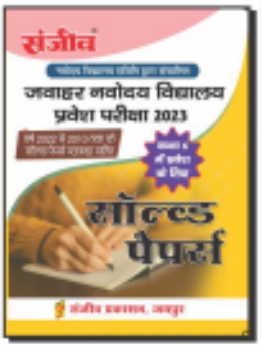

प्रभात वालिया की पुस्तकें

जी.सी. जाखड़ द्वारा लिखित पुस्तक

मनोहर सिंह कोटड़ा के मार्गदर्शन में तैयार पुस्तकें

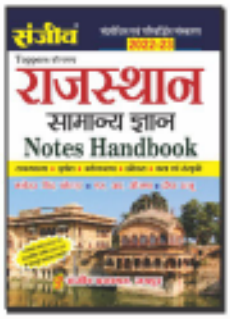

संजीव वेबसाइट से परीक्षा उपयोगी पाठ्य सामग्री निःशुल्क डाउनलोड करें।
साथ ही संजीव वेबसाइट से आप E-Book भी खरीद सकते हैं।

प्रकाशक-संजीव प्रकाशन, जयपुर

Visit us at : www.sanjivprakashan.com

SHAKUN